



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 1984/आषाढ़ 12, 1906

No. 87]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 1984/ASADHA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1984

संख्या 37/3/84-खान-1 :—खनिज गवेषण निगम की
स्थापना 21-10-1972 को निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ
एक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी :—

- (1) खनिज स्रोतों के गवेषण के कार्यक्रम का आयोजन विकास प्रबंध और कार्यान्वयन करना तथा ऐसे कार्य करना जो देश के भीतर और बाहर खनिज स्रोतों के गवेषण के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर कंपनी को सौंपे जाएं;
- (2) खनिजों के गवेषण हेतु भू-वैज्ञानिक, भू-रासायनिक तथा भूभौतिकी सर्वेक्षण करना;
- (3) खनिजों के भंडारों की पुष्टि और आकलन हेतु ड्रिलिंग और समन्वेषी खनन तथा पूर्वोक्त कार्य करना;

- (4) अन्य ऐसे कार्यक्रमों को लागू करना, प्रोत्साहित करना तथा बढ़ाना जिनके फलस्वरूप इन भंडारों की पुष्टि हो सके;
- (5) खनिज निक्षेपों का ड्रिलिंग द्वारा व्यापक सर्वेक्षण करना और निर्धारित दोहन एजेंसियों के परामर्श से समन्वेषी एवं उत्पादक खनन शुरू करना ताकि जब एजेंसियों को निक्षेपों को सौंपा जाए तो इन पर बिना विलम्ब कार्य किया जा सके।
- (6) दोहन एजेंसियों के परामर्श से खनिज भंडारों पर साध्यता रिपोर्ट तैयार करना;
- (7) खनिज गवेषण के विभिन्न क्षेत्रों में ठेकागत कार्य हाथ में लेना खनिज गवेषण से विभिन्न प्रयोजनों के लिए निगम के निदेशक मंडल द्वारा यथा-निर्धारित अनुसूचित दरों पर ड्रिलिंग तथा खनन ठेके लेना;
- (8) भारत के बाहर भारतीय कंपनी द्वारा या विदेशी कंपनी या सरकार की ओर से खनिज गवेषण के ठेके लेना, जिनकी शर्तों का निर्धारण प्रत्येक प्रकरण में केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा।

(9) वैज्ञानिक कार्य के प्रयोजन से किए गए गवेषण के दौरान प्राप्त खनिज उत्पादन कीसे कि मात्रा का बिना कोई रायल्टी अदा किए संचलन तथा निपटान करना तथा उपर्युक्त से प्राप्तिक ऐसे उत्पादन का किसी निगम या सरकारों एजेंसी या राज्य सरकार को वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा रायल्टी के भुगतान पर निपटान करना ।

2. खनिज गवेषण निगम को केन्द्र सरकार द्वारा गवेषण के लिए सौंपी गई परियोजनाएं "विकास के आधार" पर होती हैं, और इनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित दरों पर भुगतान किया जाता है। इसको कार्यविधि इस प्रकार है, कि जब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रारंभिक खोज कार्य पूरा कर लिया जाता है तो उसके बाद एक समन्वय समिति के माध्यम से व्यापक गवेषण की एक परियोजना विकसित की जाती है, इस समिति में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खनिज गवेषण निगम लिमिटेड और संबंधित उद्यम के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा, केन्द्र सरकार स्वतः भी अन्वेषण की परियोजनाएं खनिज गवेषण निगम को सौंप सकती है। भारत सरकार ने विशुद्ध कम करने की दृष्टि से वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा की है। सरकार ने तदनुसार विकास परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए वर्तमान कार्यविधि को संशोधित किया है तथा समन्वय समिति का पुनर्गठन किया है जो न केवल परियोजनाओं के तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखेगी, अपितु गवेषण के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सरकार की अपनी प्राथमिकताओं के क्रम को भी ध्यान में रखेगी।

3. पुनर्गठित समन्वय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

गठन

- | | |
|--|----------|
| 1. संयुक्त सचिव, खान विभाग | अध्यक्ष |
| (खनिज गवेषण निगम पर कार्यवाही करने वाला) | |
| 2. अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक एम० ई० सी० एल० | वैकल्पिक |
| 3. वरिष्ठ उप निदेशक (आप) जी० एस० आई० | |
| 4. उप वित्त सलाहकार, खान विभाग | सदस्य |
| 5. अधीक्षक खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो | सदस्य |
| 6. उस मंडल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या निदेशक (तकनीकी) जिसके कार्यमूखे नद पर विचार किया जाता है। | सदस्य |

4. समिति के निम्नलिखित कार्य और दायित्व होंगे :—

उपर्युक्त समन्वय समिति की तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी। खनिज गवेषण निगम विकास परियोजनाओं जिसमें केन्द्रीय सरकारों सैक्टर उपक्रमों के पट्टा क्षेत्रों के, कार्यक्रम भी शामिल हैं, के बारे में (जी० एस० आई० आदि के परामर्श के बाद) के प्रभाव समन्वय समिति के

विचारार्थ प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन प्रस्तावों के पूर्ण तकनीकी वरीर और वित्तीय प्रभाव दिए होंगे। परियोजना प्रस्तावों को, उन पर समिति की स्वीकृति के बाद खनिज गवेषण निगम द्वारा खान विभाग को मंजूरी जारी करने के लिए भेजे जाएंगे। यद्यपि खान विभाग को समिति द्वारा अनुसूचित प्रस्तावों को गुण दोष के आधार पर विचार करने का समिति की सिफारिशों को मानने और न मानने के अधिकार हैं, तथापि आशा है समिति की सिफारिशों को खान विभाग द्वारा उनके व्यापक समीक्षा किए बिना स्वीकार कर लिए जाने की आशा है। किन्तु जिस मामले में किसी परियोजना विशेष बर व्यय को स्वीकृति हेतु ई० एफ० सी० पी० आई० पी० को भेजा जाना है, वहां खान विभाग का प्रशासनिक अनुगमन यथास्थिति ई० एफ० सी० ज़ाप पी० आई० बी० नोट तैयार करेगा और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करेगा। पी० आई० बी०/ई० एफ० सी० द्वारा मंजूरी प्राप्त हो जाने के बाद ही, जैसी भी स्थिति होगी, खान विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की जाएगी।

5. खनिज गवेषण निगम समिति को सचिवालय संबंधी मदद प्रदान करेगा।

6. खनिज गवेषण निगम लि० के समुचित रिकॉर्ड रखेगा। वे प्रतिमाह बिल तैयार करेंगे, जिसमें विभिन्न शीर्षकों जैसे ड्रिलिंग खनन आदि के अन्तर्गत पूर्वं माह के अन्त तक किए गए कार्य को मात्रा, अनुमोदित प्रभार अनुसूच के संदर्भ में देय राशि आवश्यक विहित प्रमाण पत्रों सहित, दिखाया जाएगा, और तब वे बिल धनराशि जारी किए जाने हेतु सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

7. जब कभी कोई विकास कार्य हर प्रकार से पूरा हो जाएगा, तो कम्पनी एक अंतिम (पूर्ण) बिल प्रस्तुत करेगी जिसमें उक्त खोज के लिए कुल दावा राशि तथा उसमें से कम्पनी को उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित मासिक बिलों के माध्यम से प्राप्ति राशि को घटा कर शेष देय राशि दी गई होगी और उसे भुगतान हेतु सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। कथित बिल के साथ कम्पनी के निदेशक (वित्त)/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा लिखित इस आशय का एक प्रमाण पत्र होगा "कि दावा राशि किए गए वास्तविक कार्य की परिचायक है तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा उनकी सम्यक जांच कर ली गई है"। विकास कार्य से संबंधित सभी आदेश पुस्तिकाएं, कार्य पुस्तिकाएं तथा अन्य रिकॉर्ड मांगे जाने पर सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे।

8. उपर्युक्त समन्वय समिति तिमाही बैठकों के दौरान प्रत्येक अन्वेषण की प्रगति की समीक्षा करेगी और तय करेगी कि क्या उन विकास निर्माण कार्यों परिवर्तनों के साथ या बिना परिवर्तन किए जारी रखा जाए या बंद कर दिया जाए। अन्वेषण आकड़ों के मूल्यांकन की तिमाही रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।

9. इस मामले में किसी प्रकार का कठिनाई या इस प्रक्रिया की व्याख्या अथवा भुगतान का वास्तविक माप का निर्धारण हेतु समन्वय समिति/खनिज गवेषण निगम द्वारा

करण भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा जिनके आदेश मन्तिम होंगे।

10. उपर्युक्त निर्देश सूचना और मार्ग दर्शन हेतु सभी अधिकृत पक्षों के ध्यान में लाए जाएँ।

एच० एल० अत्री, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 3rd July, 1984

RESOLUTION

No. 37/3/84-MI.—Mineral Exploration Corporation Ltd., was set-up as a Limited Company on 21-10-1972 with the following main objectives :—

- (i) to plan, promote, organise and implement programme for the exploration of mineral resources and to perform such functions as the Central Government may, from time to time, assign to the Company in connection with the exploration of the mineral resources in and outside the country;
- (ii) to carry out geological, geochemical and geophysical surveys for exploration of minerals;
- (iii) to carry out drilling and exploratory mining and prospecting operations to prove/estimate the reserves of minerals;
- (iv) to undertake, encourage and promote such other activities as may lead to the establishment of such reserves;
- (v) to carry out detailed exploration of mineral prospects by drilling and, in consultation with the designated exploiting agency, take up exploratory-cum-production mining so that the deposit when handed over to that agency, can be worked without delay;
- (vi) to prepare feasibility reports on mineral prospects in consultation with the exploiting agencies;
- (vii) to undertake contract jobs in various fields of mineral exploration; to take up drilling and mining contracts for purposes other than mineral exploration on payment of scheduled rates to be fixed by the Board of Directors of the Corporation;
- (viii) to undertake contracts for mineral exploration outside India either for an Indian Company or a Foreign Company or Government on terms and conditions to be decided in each case in consultation with the Central Government;
- (ix) to transport and dispose of any quantity of mineral products, won during exploration for purposes of scientific work without paying any royalty and to dispose such production

as may be incidental thereto to a Corporation, Government agency or State Government on payment of royalty by the actual user.

2. The projects assigned by Central Government to MEC for exploration are on a "promotional basis" and paid for by the Central Government in accordance with a schedule of rates approved by it. The extant procedure is that after preliminary investigations are completed by Geological Survey of India, a project is brought up for detailed exploration through a Co-ordination Committee comprising GSI and MECL, as also a representative of the interested enterprise. In addition, the Central Government could also give projects suo motu to MECL for investigation. The present procedure has been reviewed by the Government of India with a view to reduce delays. The Government accordingly revised the procedure for clearance of promotional projects and reconstituted the Coordination Committee who would not only take note of the technical aspects of the projects but also the Governments' own order of priorities for allocating resources for exploration etc.

3. The constituted Coordination Committee will have the following composition :

COMPOSITION

1. Joint Secretary, Department of Mines (dealing with MECL) Chairman
2. Chairman-cum-Managing Director, MECL Alternate Vice-Chairman
3. Senior Dy. Director General (Op), GSI Alternate Vice-Chairman
4. Deputy Financial Adviser Department of Mines Member
5. Superintending Mining Geologist, Indian Bureau of Mines Member
6. Chairman-cum-Managing Director or Director (Technical) of the concerned organisation whose agenda item is to be considered. Member

4. The Committee shall have the following functions and responsibilities :—

The above Coordination Committee shall meet at least once in a quarter. MEC would put up proposals for promotional projects including the programme in leasehold areas of Central Public Sector Undertakings (after consulting GSI etc.) to the Coordination Committee for their consideration, giving their complete technical details and financial implications. In cases where the Committee gives its clearance, the project proposals would be sent by MECL to the Department of Mines for issue of sanction. Though the Department of Mines have the right to examine the merits of such proposals recommended by the Committee and accept or reject the recommendations of the Committee. It is expected that the Committee's recommendations would be accepted by the Department of Mines without elaborate examination again at their end. However, in case, where the expenditure on a particular project calls for reference to EFC/PIB, then the Administrative Section of the Department of Mines would prepare

and EFC Memo|PIB Note as the case may be and would obtain necessary clearance in the matter. The sanction from Department of Mines would be issued only after clearance by PIB|EFC, as the case may be, is obtained.

5. MECL shall provide the Secretariat assistance to the Committee.

6. MECL shall maintain a proper record of the investigations. They would prepare bills every month showing therein the quantum of work done under different headings such as drilling, mining etc. till the end of the previous month; the amount payable in terms of the approved schedule of charges alongwith necessary prescribed certificates and submit them to Government for the purpose of release of funds.

7. As and when any promotional work is completed in all respects, the Company shall provide a final bill indicating the total claims for the said investigation minus the amount paid to the Company through the monthly bills referred to in para 4 above and thus showing the balance amount payable and submit it to the Government for payment. The said bill shall be accompanied by a certificate recorded by the

Director (Finance) Financial Adviser & Chief Account Officer of the Company to the effect that "the claim represents the actual work done and the same has been test checked by Internal Audit." All order books, work books and other records pertaining to promotional work shall be made available to Government whenever required.

8. The Co-ordination Committee referred to above shall also review the progress of each investigation during the quarterly meeting and decide whether these promotional works should be continued with or without modifications or be stopped. A quarterly report on the evaluation of investigation data should be sent to the Government.

9. In case of any difficulty in this matter or the interpretation of this procedure or deciding the actual quantum of payment the matter will be referred by the Co-ordination Committee|MEC to the Government of India whose orders shall be final.

10. The above instructions may be brought to the notice of all concerned for information and guidance.

H. L. ATTRI, Under Secy.